



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11072024-255350
CG-MH-E-11072024-255350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]
No. 508]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2024/आषाढ 20, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2024/ASHADHA 20, 1946

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(मानव संसाधन प्रबंधन विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 11 जुलाई, 2024

नं. एचओ:एचआरओपीएस:116:1540 (ई): बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (2) के खंड (एफ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श कर और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से एतद्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- (1) इन विनियम को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन), विनियम, 2024 के नाम से जाना जाएगा।
(2) इन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियमन 2 में, उप-विनियमन (एस) में, खंड (डी) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
बशर्ते यह भी कि नवंबर, 2012 के पहले दिन से लागू विशेष भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।
बशर्ते यह भी कि ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 नवंबर 2017 को बैंक की सेवा में थे और और जिनकी अवरुद्ध वेतन वृद्धि/यों को उनके अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनर्समायोजन

किया गया है, पेंशन के प्रयोजनों हेतु 1 नवंबर 2017 से इस प्रकार की संशोधित अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए अनुमानिक रूप से पात्र होंगे लेकिन इस प्रकार के पुनर्समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तारीख, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

3. उक्त विनियम के विनियमन 22 में, उप-विनियमन (1) में, निम्नलिखित परंतुक को शामिल किया जाएगा:
"बशर्ते यह कि ऐसे कर्मचारी जो बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक कामगार हैं या पारिश्रमिक वेतनमान के आधार पर अंशकालिक रूप से कार्य करते हैं, को सेवा से बाहर किए जाने पर उनकी पिछली पूर्ण सेवा हेतु जब्ती नहीं की जाएगी और वे पेंशन संबंधी लाभ के लिए पात्र होंगे"।
4. उक्त विनियम के विनियमन 36 में, खंड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, यथा:-

"जी) अंशकालिक कर्मचारी के अतिरिक्त, जो कर्मचारी नवंबर, 2017 के पहले दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें तीन हजार नौ सौ पचासी रुपये प्रति माह और नवंबर, 2017 के पहले दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पारिश्रमिक वेतनमान का 1/3 प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति माह, पारिश्रमिक वेतनमान का 1/2 प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में दो हजार रुपये प्रति माह और पारिश्रमिक वेतनमान का 3/4 प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रति माह होगा।

5. उक्त विनियम के विनियमन 40 में –

(ए) उप विनियमन (1) में

- (i) खंड (बी) में निम्नलिखित प्रथम परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते यह कि पुत्र या पुत्री (विधवा/ तलाकशुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन उस समय समाप्त कर दी जाएगी/ लागू नहीं रहेगी जब पात्र पुत्र/ पुत्री की आय सरकारी/ निजी क्षेत्र में नियोजन/ स्व-रोजगार आदि से रु. 12000 प्रति माह से अधिक हो जाएगी"

- (ii) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(सी) माता-पिता के मामले में पारिवारिक पेंशन उस समय समाप्त कर दी जाएगी/ लागू नहीं रहेगी जब माता-पिता में से किसी एक की या दोनों की सकल आय सरकारी/ निजी क्षेत्र में नियोजन/ स्व-रोजगार आदि से रु.12,000 प्रति माह से अधिक हो जाएगी"

(बी) उप विनियमन (4) में

- (i) खंड (ए) में, उप-खंड (vi) के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, यथा:-

"(vii) कर्मचारियों, अधिकारियों एवं कामगारों दोनों, के संबंध में, उन कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति/ मृत्यु नवंबर, 2017 के पहले दिन को या उसके बाद हुई है, प्रति माह रुपये छब्बीस हजार पाँच सौ साठ केवल।"

बशर्ते कि अप्रैल 2021 के पहले दिन को और उसके बाद से, उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होंगे और उपर्युक्त श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि इस विनियम के विनियम 39 के उप-विनियमन (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के बाद निम्नलिखित खंडों को जोड़ा जाएगा, यथा:-

“(vii) कर्मचारियों, अधिकारियों एवं कामगारों दोनों, के संबंध में, उन कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु नवंबर, 2017 के पहले दिन को या उसके बाद हुई है, प्रति माह रुपये छब्बीस हजार पाँच सौ साठ केवला”

बशर्ते कि अप्रैल 2021 के पहले दिन को और उसके बाद से, उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होंगे और उपर्युक्त श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियमन 39 या खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) या जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

(iii) खंड (सी) में, उप खंड (vi) के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, यथा:-

(vii) “अधिकारियों एवं कर्मचारियों दोनों के संबंध में, उन कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति/ मृत्यु नवंबर, 2017 के पहले दिन को या उसके बाद हुई है, प्रति माह रुपये तेरह हजार दो सौ अस्सी केवल”

बशर्ते कि अप्रैल 2021 के पहले दिन को और उसके बाद से, उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होंगे और उपर्युक्त श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

6. उक्त विनियम के परिशिष्ट II के लिए खंड (4) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:

(4) दिनांक 01.05.2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में महंगाई राहत, सिरीज़ 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगी या प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उपर्युक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.18% की दर से की जाएगी।

बशर्ते जो कर्मचारी 01 नवंबर 2002 को या उसके बाद परंतु 30 अप्रैल 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके मामले में 01 मई 2005 को या तब से महंगाई राहत इस खंड के अनुसार देय होगी।

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी जो 01 नवंबर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके मामले में महंगाई राहत, सिरीज़ 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 2836 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगी या प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उपर्युक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.15% की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी जो नवंबर 2012 के पहले दिन को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके मामले में महंगाई राहत, सिरीज़ 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 4440 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगी या प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो। उपर्युक्त प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.10% की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके मामले में महंगाई राहत, सिरीज़ 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 6352 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी,

जैसा भी मामला हो। उपर्युक्त प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.07% की दर से की जाएगी।"

7. उक्त विनियमन के परिशिष्ट III में खंड (एफ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा: -

जी) 01 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में:

क्रम सं.	प्रति माह वेतनमान	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(i)	रु.15,880 तक	'वेतन' का 30% मूल परिवार पेंशन होगी तथा इसके साथ उन भत्तों का 30% जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। बशर्ते कि मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग न्यूनतम रु. 3,985/- प्रतिमाह हो।
(ii)	रु. 15,881 से रु. 31,760 तक	'वेतन' का 20% मूल परिवार पेंशन होगी तथा इसके साथ उन भत्तों का 20%, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। बशर्ते कि मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग न्यूनतम रु. 4,900/- प्रतिमाह हो।
(iii)	रु. 31,760 से अधिक	'वेतन' का 15% मूल परिवार पेंशन होगी तथा इसके साथ उन भत्तों का 15%, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। बशर्ते कि मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग न्यूनतम रु. 6365/- प्रतिमाह तथा अधिकतम रु.13,280/- प्रतिमाह हो।

(एच) 1 अप्रैल, 2021 को तथा उस तारीख से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं रहेंगे और उक्त खंडों में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारी और कर्मचारियों दोनों) के संबंध में, 'वेतन' का 30% मूल परिवार पेंशन होगी इसके साथ उन भत्तों का 30% जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी।

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियम में दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और शीर्ष स्तरीय कामगार संघ एवं बैंकों के अधिकारी संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौते और संयुक्त नोटों की सहमत नियम व शर्तों के अनुसार हैं। अतः इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शैलेन्द्र सिंह, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./278/2024-25]

नोट: मूल विनियम 29 सितंबर, 1995 को अधिसूचना क्रमांक बीओबी:एचओ:पीईएन:87/780 के तहत भारत के राजपत्र के भाग III के खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना क्रमांक एचओ:एचआरएम:पीईएन:115:3263(ई) द्वारा संशोधित किए गए।

BANK OF BARODA

(Human Resources Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2024

No. HO:HROPS:116: 1540 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Baroda after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bank of Baroda (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (s), in clause (d), the following provisos shall be inserted, namely:—
“Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:
Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay, shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later.”
3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: —
“Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits.”
4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —
“(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of a part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017.”
5. In regulation 40 of the said regulations,—
 - (a) in sub-regulation (1),—
 - (i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment.”;
 - (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
“(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self – employment exceeds rupees twelve thousand per month.”;
 - (b) in Sub-regulation (4),—
 - (i) in clause (a), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely: —
“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:
Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.”;

(ii) in clause (b), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.”;

(iii) in clause (c), after sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely:—

“(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6. In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4), the following shall be substituted, namely:—

“(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension.”.

7. In Appendix-III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of pay per month	Amount of monthly Family Pension
(1)	(2)
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent. of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

SHAILENDRA SINGH, CHIEF GENERAL MANAGER

[ADVT.-III/4/Exty./278/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* notification number BOB:HO:PEN:87/780, dated the 29th September,1995 and amended *vide* the notification number HO:HRM:PEN:115:3263(E), dated the 18th October,2023.